डिजीटल पत्र
दैनिक
कांग्रेस दर्पण

पटना, 20 जुलाई, शनिवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना - 10

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर आक्रोश जताया

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर आक्रोश जताया है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साझी विरासत पर हमला है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने इस आदेश को तुरंत वापस लेने और इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है।

प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।"

इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर रोष प्रकट किया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति-निंदनीय।

बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर आने वाली दुकानों और रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी नाम की नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

जन आक्रोश मार्च को सफल बनाने में अहम भूमिका निभायें सेवा दल के कार्यकर्ता : डॉ0 संजय

बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जन आक्रोश मार्च में भाग लेने का सेवा दल का आह्वान

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

एनडीए सरकार में बिहार राज्य को बेलगाम और बदहाल क़ानून व्यवस्था तथा अपराध और अपराधियों को मिली खुली छूट के खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों में 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन के जन आक्रोश मार्च को सेवा दल के कार्यकर्ता पूरे जोश से जुट जायें।

इस मार्च को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा जारी पत्र के आलोक में बिहार प्रदेश सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डा० संजय यादव ने सेवा दल कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए। इस आशय की जानकारी देते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष डॉ० संजय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है जिसमें 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में इंडिया गठबंधन के बैनर तले जन आक्रोश मार्च निकालेंगे।

इस आक्रोश मार्च में राज्य में खराब हुए कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस जन आक्रोश मार्च में सेवा दल के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और प्रदेश की निरंकुश सरकार को न्याय और कानून का राज स्थापित करने को अल्टीमेटम देंगे।

राजनांदगांव सांसद पर कार्रवाई के लिए पूर्व CM बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष से की शिकायत

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष याचिका लगाई है। उन्होंने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल, सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान भूपेश बघेल को लेकर टिप्पणी की थी। महादेव सट्टा मामले को लेकर आरोप लगाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सांसद संतोष पांडेय ने महादेव सट्टा एप को लेकर लोकसभा में जो गलत बयानी की है, उसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। उम्मीद है न्याय मिलेगा और सांसद बयान के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

दरअसल, सांसद संतोष पांडेय ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि राहुल गांधी सोमवार को बार-बार भगवान शंकर की तस्वीर संसद में दिखा रहे थे। भगवान भोलेनाथ हैं। आपने और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने पूरे प्रदेश को निपटा दिया और लोकसभा चुनाव में भी निपट गए। वो महादेव के नाम पर सट्टा चला रहे थे।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री छह हजार करोड़ का सट्टा चला रहे थे। भगवान शंकर को आसानी से ना लें और बात-बात पर फोटो दिखाने की कोशिश ना करें। सांसद के इस बयान पर भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने सवाल किया था कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद एप पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर दो जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की थी कि इस निराधार आरोप को संसद की कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही गलत तथ्यों के आधार पर संसद में गैर-मौजूद किसी व्यक्ति पर दोषारोपण करने के लिए सांसद के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी लिखी थी।

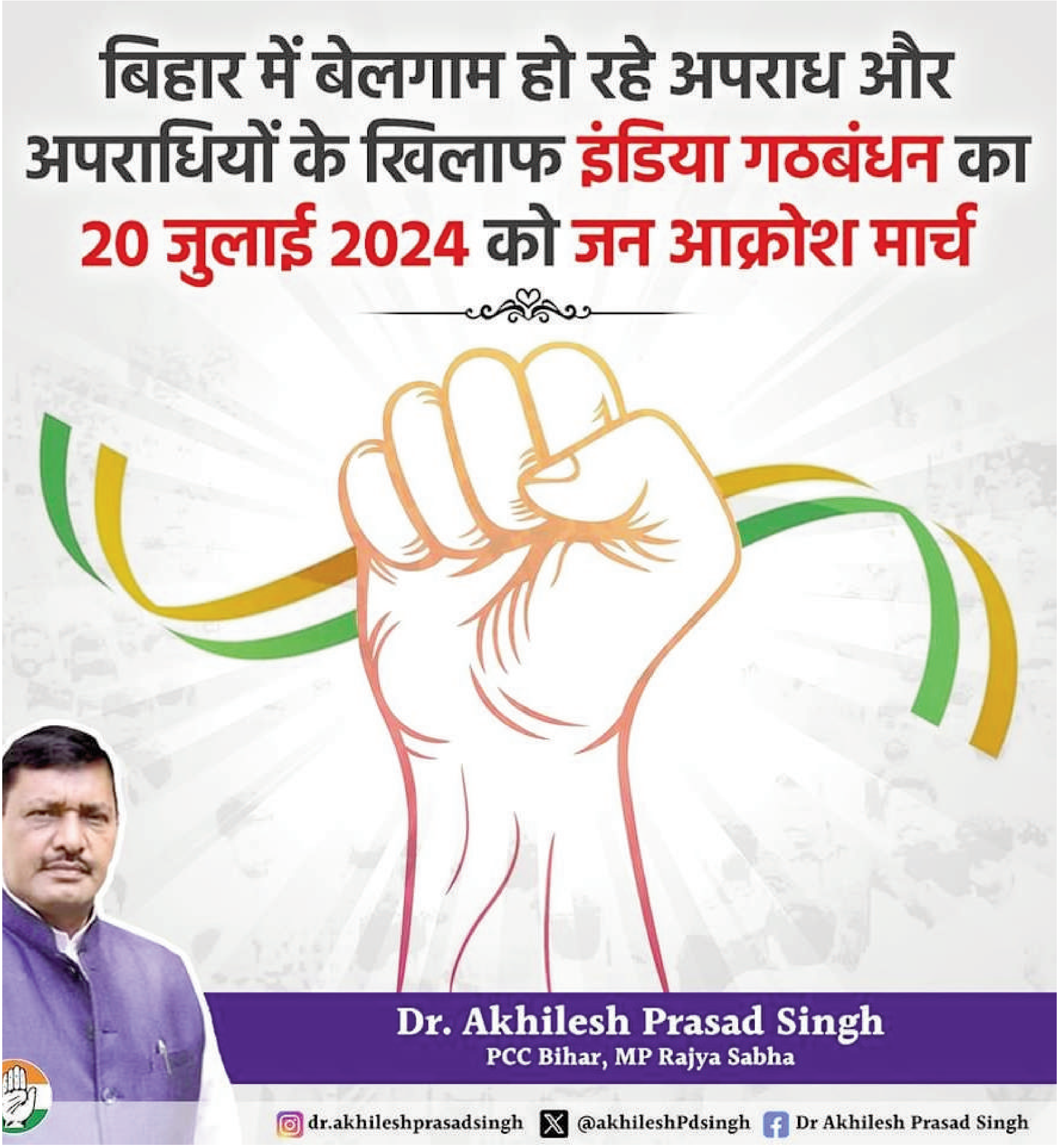

राज्य में बेलगाम हो रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों द्वारा बिहार प्रदेश के सभी जिलों में 20 जुलाई 2024 को जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, साथ ही आक्रोश मार्च के तहत राज्य में खराब हुए कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से मिलकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है?

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

▪ कांवड़ यात्रा के रूट पर फल सब्ज़ी विक्रेताओं व रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना आवश्यक होगा।

▪ यह मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का, या दोनों का, हमें नहीं मालूम।

▪ जो लोग यह तय करना चाहते थे कि कौन क्या खाएगा, अब वो यह भी तय करेंगे कि कौन किस से क्या ख़रीदेगा?

▪ जब इस बात का विरोध किया गया तो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाल लिखा जाता है तब तो आप विरोध नहीं करते।

▪इसका जवाब यह है कि जब किसी होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी भी लिखा होता है तब भी हम होटल के मालिक, रसोइये, वेटर का नाम नहीं पूछते।

▪किसी रेहड़ी या ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, झटका, हलाल या कोशर लिखा होने से खाने वाले को अपनी पसंद का भोजन चुनने में सहायता मिलती है।

लेकिन ढाबा मालिक का नाम लिखने से किसे क्या लाभ होगा?

▪भारत के बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू हैं। क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? ठीक वैसे ही क्या किसी अल्ताफ़ या रशीद द्वारा बेचे गए आम अमरूद गोश्त तो नहीं बन जाएँगे।

श्री पवन खेड़ा

कांग्रेस सेवादल विचारक तैयार करता है,जबकि भाजपा प्रचारक तैयार करती है

कांग्रेस सेवादल विचारक तैयार करता है,जबकि भाजपा प्रचारक तैयार करती है।

वो झाड़ू लगाने वाले,कालीन बिछाने वाले,कुर्सियां व्यवस्थित करने वाले सफाई करने वाले कार्यकर्ता बनाते हैं!

आज @CongressSevadal कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी बन कर खड़ा है।

: श्री @LaljiDesaiG जी

कांग्रेस सेवादल ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी गौरव यात्रा का आयोजन 2022 में किया था, जिसका समापन 1 जून 2022 को दिल्ली में राजघाट पर हुआ था।

समापन समारोह में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी मुख्य अथिति के रूप में उपस्थित रहीं थीं। वो सेवा दल के कार्यकर्ताओं से मिली और उनका मनोबल बढ़ाया था।

उसी समापन समारोह की कुछ यादें ले का एक बार फिर उपस्थित हुए हैं।

देखिए सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी से खास बात।

आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता हो तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

उत्तराखंड कांग्रेस ने दो उपचुनाव जीते जिनका श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा जी संग सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवालदल, वॉर रूम, अल्पसंख्यक विभाग, एससी विभाग, ओबीसी विभाग के साथ सभी कार्यकर्ताजनो को जाता है।

लेकिन कुछ साथी जो मंगलोर, बद्रीनाथ के प्रत्याशियो के साथ दिन रात सोशल मीडिया टीम के रूप में मेहनत कर रहे थे उनका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे बीते कल के स्वागत कार्यक्रम में मा० अध्यक्ष श्री करन माहरा जी के संग अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी सोशल मीडिया के कार्य की सराहना कर सोशल मीडिया का आभार व्यक्त करा।

बद्रीनाथ विधानसभा की टीम से प्रभारी श्री सतीश चंद्र ढिमरी, सह प्रभारी श्री गौरव, श्री अंकित फरस्वान और मंगलौर विधानसभा की टीम से प्रभारी शाकिर सुल्तान सह प्रभारी नवाज काजमी जी ने अति उत्तम कार्य कर जीत में अपनी भागीदारी निभाई इसके उपरांत कार्यालय की टीम में श्री अनुराग मित्तल, श्री पुनीत चौधरी, श्री आशीष नौटियाल, भाई जफर अब्बास के संग प्रिया जायसवाल ने और अन्य सभी सोशल मीडिया के साथियों भी दिन रात मेहनत कर इस चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करी।

आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद व आभार।

भारतीय युवा कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

पलामू जनपद के विश्रामपुर विधानसभा में भारतीय युवा कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक श्री अजीत कुमार तिवारी ने कार्यकर्ताओ को आगामी विधानसभा चुनाव की ज़िम्मेदारी देते हुए जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए कहा।

विधानसभा स्तरीय बैठक में सभी प्रखण्ड स्तरीय कमेटी को सत्यापित कर कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी।

बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष श्री गुलाम नबी के द्वारा की गई तथा जिलाध्यक्ष श्री परवेज अली ने कहा कि युवा कांग्रेस पूरे जिले में सक्रिय है और लगातार जनसेवा कर रहा है साथ ही प्रदेश महासचिव श्री अभिषेक तिवारी ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है।

प्राइवेट नौकरियों में कोटा पर अड़ी कर्नाटक सरकार, लोकल आरक्षण देकर रहेंगे

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

बेंगलुरु
कर्नाटक में निजी सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले बिल को फिर राज्य सरकार ने रोक दिया है। इस मामले पर खूब विवाद हुआ था और इंडस्ट्री के दिग्गजों ने पलायन तक की चेतावनी दी थी। इसके बाद सरकार ने कदम पीछे तो खींच लिए हैं, लेकिन अब भी अपने रवैये पर अडिग है। सिद्धारमैया सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने बातचीत में कहा कि अभी हो या फिर कुछ वक्त लगे, लेकिन यह आरक्षण तो लागू किया जाएगा। प्रियांक खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं और कर्नाटक सरकार में आईटी मंत्री हैं।

प्रियांक ने कहा, 'फिलहाल इंडस्ट्री के बीच थोड़ा भ्रम की स्थिति है। इसलिए प्रस्ताव को फिलहाल रोका है। हम उद्योग जगत के लोगों से बात करेंगे। उसके बाद फैसला लिया जाएगा। राज्य को लोगों का स्थानीय नौकरियों पर पहला अधिकार है।' उन्होंने कहा कि निजी नौकरियों में आरक्षण के बिल पर सभी मंत्रालयों से बात की जाएगी। फिर उनकी राय को भी इसमें शामिल किया जाएगा। खरगे ने कहा, 'कानून के अनुसार ही सब कुछ होगा। अन्यथा इसे चुनौती मिलेगी। हरियाणा का ही देख लीजिए। उन लोगों ने भी कानून बनाया था। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते।'

बता दें कि हरियाणा सरकार ऐसा ही प्रस्ताव लाई थी, जिसमें कहा गया था कि 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण लागू होगा। ऐसी 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को ही दी जाएंगी। इस बिल को राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन फिर इसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिल को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने चुनौती दी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दलील दी गई थी कि यह रोजगार में समानता के अधिकार को छीनता है, जो संविधान में दिया गया है।

इसके अलावा इससे स्किल आधारित नौकरियों में दिक्कत आएगी और अकुशल लोगों को भी रखना पड़ेगा। याचियों का कहना था कि अहम पदों पर पूरे देश से अप्लाई करने की छूट होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में विचार करने पर इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि कोई भी राज्य नौकरियों में यह देखकर भेदभाव नहीं कर सकता है कि वह किसी खास राज्य का नहीं है अथवा है। ऐसा करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।

24 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा घेराव

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

विष्णुदेव की सरकार छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, कानून व्यवस्था इनके हाथों से निकल चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटीलेटर पर है।

आगामी 24 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा घेराव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बुलंद की जाएगी।

उपरोक्त विरोध प्रदर्शन की तैयारी हेतु प्रदेश अध्यक्ष श्री Deepak Baij जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी, रायपुर शहर ग्रामीण, धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कर आगे की रूपरेखा तैयार की गई।

- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

बजट से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, महंगाई-बेरोजगारी को लेकर नहीं उठाए जा रहे कदम

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

नई दिल्लीः कांग्रेस ने कहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश करेंगी और इसको लेकर वह उद्योगपतियों, बैंकर्स, किसान संगठनों से बात कर चुकी है, लेकिन देश में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, महंगाई और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है. जिसे कम करने के लिए उनके इरादे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बड़ा संकट यह है कि देश की एक फीसदी आबादी के पास लगभग आधा संपत्ति है जिसके कारण गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ रही है और बेरोजगारी का हल नहीं निकल रहा है. हालात यह है कि नौकरियां नहीं हैं और देश में नौकरियां सिर्फ संविदा पर आधारित हो गई हैं. संविदा नौकरियों की दर दोगुनी से ज्यादा हो गई है और महंगाई आसमान छू रही है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार फिलहाल कदम उठाते नजर नहीं आ रही है.

48 प्रतिशत परिवार आर्थिक तंगी से परेशान

उन्होंने कहा, आज देश में आर्थिक असमानता की दर ब्रिटिश राज से भी बदतर है. इस देश की एक प्रतिशत आबादी का देश की 40 प्रतिशत संपत्ति पर नियंत्रण है. जिसके कारण अमीर और अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है. क्या यह बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा. देश के 48 प्रतिशत परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. लोगों की आय कम हुई है और वे बचत का सहारा लिए जीवन जी रहे हैं. आज देश की हालत -'आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया' हो गया है. उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण जी

अपना सातवां बजट पेश करेंगी. इस बजट को बनाने से पहले उन्होंने कुछ उद्योगपतियों, बैंकर्स, किसान संगठनों से मुलाकात कर विचार-विमर्श किया है, लेकिन क्या वे उन परिवारों से मिली हैं, जो दिन में तीन वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं. क्या वे उन महिलाओं से मिली हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं. क्या वे उन किसानों से मिली हैं, जो फसल का सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. क्या वे उन युवाओं से मिली हैं, जो पेपर लीक से प्रताड़ित हैं. क्या वे असल हिंदुस्तान से मिली हैं. ये स्पष्ट है कि वे उनसे नहीं मिली हैं. ये बजट चंद पूंजिपतियों को और अमीर बनाने के लिए बनाया जा रहा है.

नड्डा जी ने वही किया जो करते यानी "कुछ नहीं"

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

गाजियाबाद के इंदर बजरंगी भाजपा OBC मोर्चा के महानगर महामंत्री हैं। उनकी माता जी हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं।

वह दिल्ली में बेहतर इलाज के लिए गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग का लिखा लेटर लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के आवास पहुंचे।

नड्डा जी ने वही किया जो करते यानी "कुछ नहीं"

आज भाजपा पदाधिकारी ने अपने ट्वीट में भाजपा के संगठन और सरकार की पोल खोलते हुए खुद को ठगा हुआ बताया।

बीजेपी अध्यक्ष / केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आपके पास तो संगठन और सरकार दोनों की पावर है, तो आपको कौन सी शक्ति रोक रही थी भाजपा पदाधिकारी की मदद करने के लिए?

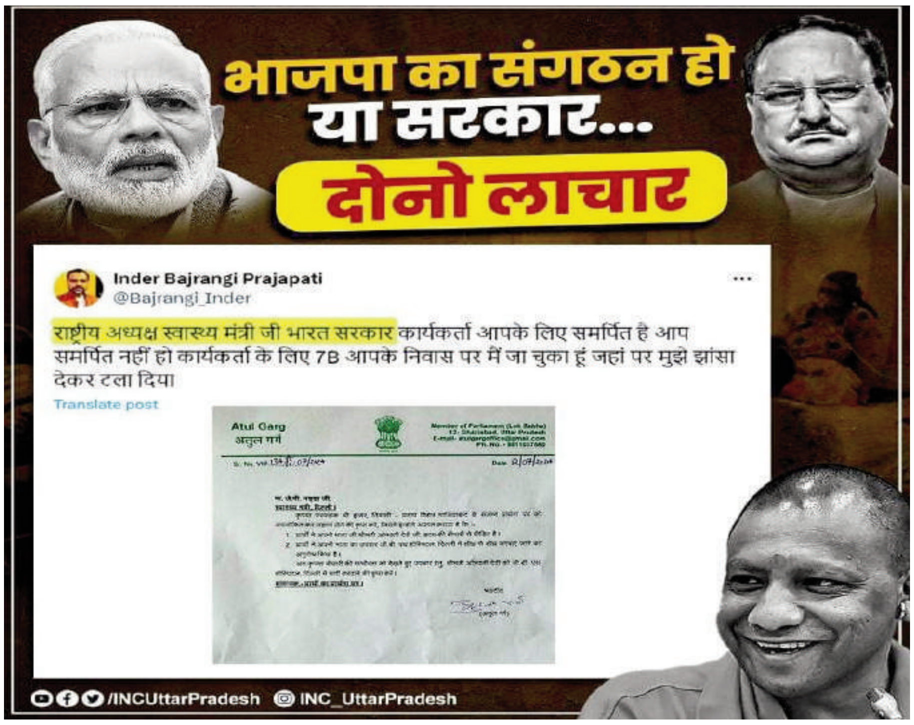

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कतरास कांग्रेस प्रधान कार्यालय में युवा कांग्रेस की बैठक

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

दिनाँक 19/07/2024 को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा कॉंग्रेस की एक बैठक कतरास कॉंग्रेस प्रधान कार्यालय में सम्पन्न हुई,बैठक की अध्यक्षता युवा कॉंग्रेस के बाघमारा विधानसभा अध्यक्ष विशाल महतो एवं संचालन नगर अध्यक्ष विकास सिंह ने किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा कॉंग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक करुण नंदन पासवान,युवा कॉंग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष कुमार गौरव तथा युवा कॉंग्रेस के धनबाद जिला के सह प्रभारी विकी कुमार जी उपस्थित थे !कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कॉंग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक करुण नंदन पासवान ने कहा की झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक युवा कॉंग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचाए साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवा कॉंग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता तैयार रहें।जिला अध्यक्ष कुमार गौरव जी ने दावा किया की पुनः झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी,युवा वर्ग भाजपा के झूठे वायदे से सावधान रहें !

बैठक मे मुख्य रूप से विशाल महतो,विकास सिंह,बाघमारा विधानसभा युवा कॉंग्रेस प्रभारी सोनू यादव,जिला महासचिव विकी कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अजय महतो,योगेश्वर रॉय, अनीता देवी,फूल देवी,योगेन्द्र महतो,कमलेश पाठक,राजू सिंह,निर्मल महतो,दिनेश महतो, धीरज कुमार,राजू तुरी आदि लोग उपस्थित थे !

भाजपा ने चंद उद्योगपतियों की जेब भरने का औजार बना दिया

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1969 में आज ही के दिन देश के 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मकसद था कि बिना मुनाफे की चिंता किए बैंक हमारे गांवों तक पहुंचें ताकि आम गरीब और वंचित लोगों को भी बैंकिंग का लाभ मिल सके।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं खोली गईं। छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों और आम जरूरतमंद लोगों को कर्ज मिलना शुरू हुआ। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा। बैंकों के जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचने लगा। लाखों लोगों को नौकरियां मिलीं। कृषि और औद्योगिक विकास का रास्ता खुला।

जबसे केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, सरकारी बैंकों के निजीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ, भाजपा के दस साल के कार्यकाल में लगभग छह लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड सामने आया है। जिन बैंकों को कांग्रेस ने जनता के सशक्तिकरण का माध्यम बनाया, उन्हें भाजपा ने चंद उद्योगपतियों की जेब भरने का औजार बना दिया है। यह देशहित में नहीं है।

नौकरी आरक्षण विधेयक की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की आलोचना

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने के विधेयक की कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य और सांसद शशि थरूर ने आलोचना की। उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक और नासमझी भरा फैसला बताया। साथ ही उन्होंने विधेयक को पारित करने से रोकने पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की सराहना की।

तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि कर्नाटक यह फैसला मूर्खतापूर्ण था। अगर हर राज्य ऐसा कानून लाने लगा तो यह असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और यात्रा करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा सरकार भी ऐसा ही एक विधेयक लाई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर

दिया था। थरूर बोले कि पता नहीं कर्नाटक सरकार ने क्या सोचकर और किस आधार पर यह विधेयक बनाया। अगर यह कानून आता है तो कर्नाटक के व्यवसाय तमिलनाडु और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों में स्थानांतिरत हो जाएंगे।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय और लिपिकीय नौकरियों को कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था। सरकार ने इस मसौदे को 'कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक, 2024' नाम दिया। इस विधेयक को सोमवार को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। विधेयक में कहा गया था कि प्रबंधन श्रेणी में 50 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। वहीं गैर-प्रबंधन श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुए हैं और 15 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं। दूसरी शर्त यह भी थी कि उम्मीदवार को कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए और इसने कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

कई उद्योगपतियों ने बुधवार को इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और आशंका जताई कि टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। विधेयक पर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने बुधवार दोपहर को ट्वीट में कहा कि कैबिनेट बैठक में राज्य के उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधक पदों पर 50 फीसदी जबकि गैर प्रबंधक पदों पर 75 फीसदी आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। जब विरोध नहीं थमा तो बुधवार रात को ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया कि विधेयक को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सीएमओ ने आगे कहा कि आगामी दिनों में इस विधेयक की समीक्षा की जाएगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा।

आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

जनपद वाराणसी में जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष /फ्रंटल संगठनों के प्रभारी श्री विश्व विजय सिंह जी ने NSUI, फिशरमैन कांग्रेस, युवा कांग्रेस, आउटरीच प्रकोष्ठ एवं उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के बनारस मण्डल से सम्बंधित प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा एवं विस्तार पर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।

इस दौरान ठरवकपूर्वी जोन के अध्यक्ष ऋषभ पांडेय जी, फिशरमैन कांग्रेस पूर्वी जोन के चेयरमैन देवेंद्र निषाद जी, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, युवा कांग्रेस आउटरीच के अध्यक्ष आदिल खान जी मौजूद रहे।